



हमारा दून

संक्षिप्त समाचार

नगर निगम दून ने 40 लाख सीएम कोष को दिए संवाददाता देहरादून। कोविड-19 के दृष्टिगत नगर निगम दून ने 40 लाख रुपए का चेक नगर निगम बोर्ड फंड से एवं 11 लाख रुपए का चेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु दिए हैं। यह चेक मेरय सुनील उनियाल गामा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को सौंपा। इस अवसर पर नगर आयुक्त देहरादून श्री विनय शक्तर पांडे भी उपस्थित थे। भारतीय सेंसर बोर्ड के चेयरमैन एवं भारतीय सिनेमा के गीतकार श्री प्रसून जोशी ने भी कोविड-19 के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 10 लाख रुपए दिए हैं।

विस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया एक माह का वेतन

संवाददाता देहरादून।

उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सहयोग करने हेतु तथा कोरोना महामारी से निपटने एवं जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना वायरस एक खतनाक संक्रमण है। इसके खाले के लिए काफी सारे धन की जरूरत है।

निधन पर गहरा दुःख

जाताया

संवाददाता देहरादून। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य शारदा त्रिपाठी के पति की मृत्यु हो गयी है जिस पर आयोग की अध्यक्ष ऊपर नेगी ने दिवंगत आत्मा के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सन्देश दिया की दुःख की इस घड़ी में वह देहरादून में न होने व हरियाणा में लॉकडाउन में फंसे होने के कारण शारदा के शोक संतप्त परिवार के साथ नहीं हूं। यहां जारी एक बयान में नेगी ने कहा है कि परन्तु मेरी संवेदनायें उनके परिवार के साथ हैं। परम पिता ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे।

कोरोना वायरस से बचाव को जागरूकता कार्यक्रम चलाया संवाददाता देहरादून। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के तत्त्वावधान में देश में फैल रही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस अवसर पर जिसमें लोगों को मास्क व सेनिटाइजर वितरित किये जा रहे हैं साथ ही लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। राजधानी में विभिन्न सामाजिक संस्थायें भी पूरी तरह से कोरोना वायरस से बचाव के लिए सक्रिय हैं। इस अवसर पर लॉकडाउन में निल छह घंटे की छूट के दौरान लोगों को जानकारियां प्रदान किया जा रही हैं।

केद्र सरकार द्वारा सांसद निधि में दो साल तक रोक लगाया जाना गलतः प्रीतम

संवाददाता देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए मलिन बस्तियों में निवास कर रहे गरीब तबके के लोगों को खासतौर पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे से पूर्व घाटाघर पर इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को अपनी बाईट देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए जहां सरकार के साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों एवं अन्य पार्टियों के पदाधिकारी जहां एकजूत हैं वहां कांग्रेस भी पूरी तरह से सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस भी व्यापक स्तर पर इस दिशा में अपने स्तर से कार्य कर रही है और जरूरतमंद व असहायों को लगातार भोजन व राशन का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा सांसद निधि में दो साल तक रोक लगाया जाना गलत है इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बहाल किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस समय से कार्यक्रम की खास जरूरत है इसके माध्यम से लोगों की सेवा व विकास कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है सांसद निधि व विधायक निधि को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है इस व्यवस्था को यथावत रखने की आवश्यकता है।

स्प्रे से व्यक्ति का पूरा शरीर किया जा रहा है सैनिटाइज़

नया तरीका

संवाददाता

हरिद्वार। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हाथों को सैनिटाइज़ करने को कहा जा रहा है, लेकिन ज्वालापुर सभी मंडी आने वाले लोग सैनिटाइज़र में स्नान करने के बाद ही अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। दरअसल, मंडी प्रशासन ने प्रवेश द्वारा पर सैनिटाइज़िंग टनल बनाई है। टनल में लगातार सैनिटाइज़र का स्प्रे किया जा रहा है। ऐसे में मंडी प्रशासन ने प्रवेश करने से पहले लोगों को टनल से गुजरना पड़ रहा है। वहां स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था बिलकुल भी व्यवहारिक नहीं है। इससे बेहतर होगा कि लोगों के हाथ सैनिटाइज़ कराए जाएं।

कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर किए गए लॉकडाउन के चलते ज्वालापुर सभी मंडी में रोजाना हजारों की संख्या में

मंडी प्रशासन हरिद्वार ने बनाया गया सैनिटाइज़र टनल, प्रवेश से पहले स्नान

मंडी प्रशासन ने फुटकर ग्राहकों पर रोक लगा दी



एथो नॉल, सो डियम हाइपोक्लोराइड और ग्लिसरीन आदि शामिल हैं।

मंडी समिति ज्वालापुर के सचिव दिव्यजय सिंह देव ने बताया कि यह लिकिवड मानव शरीर को सैनिटाइज़ करने के लिए उपयुक्त है। मंडी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सैनिटाइज़िंग टनल से होकर गुजरना जरूरी है। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए टनल से एक-एक व्यक्ति को गुजारा जा रहा है। इस व्यवस्था से मंडी में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में काफी मदद मिलेगी।

उत्तराखण्ड में जमाती बने हुए हैं मुसीबत का सबब

चुनौती

- डीजीपी की चेतावनी के बाद सामने आए 180 जमाती
- दो के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा



41 जमाती चोरी छुपे उत्तराखण्ड पहुंचे उन पर भी मुकदमा दर्ज

अशोक कुमार महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था ने बताया कि एक से पांच अप्रैल के बीच 41 जमाती चोरी छुपे उत्तराखण्ड पहुंचे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

उत्तराखण्ड में जमाती मुसीबत का सबब बने हुए हैं। अबतक दिल्ली और अन्य शहरों से लौटे जमातियों में रोजाना संक्रमण की सप्तिहार के जमाती सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक हरिद्वार जिले के हैं, जिनकी संख्या 151 है। इसके अलावा नैनीताल में 12 देहरादून में 9 और पौड़ी में 8 जमाती सामने आए हैं।

कोरोना वायरस से लौटे जमाती सामने आए हैं। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि लक्सर में चार ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने जमातियों को छह अप्रैल तक खुद सामने आए और इसके बाद पकड़े जाने पर हत्या का प्रयास की धारा लगाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रदेश में 180

की पुष्टि होने से उत्तराखण्ड के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। इसे देखते हुए डीजीपी अनिल रत्नानी ने जमातियों को छह अप्रैल तक खुद सामने आए और इसके बाद पकड़े जाने पर हत्या का प्रयास की धारा लगाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रदेश में 180

जमाती सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक हरिद्वार जिले के हैं, जिनकी संख्या 151 है। इसके अलावा नैनीताल में 12 देहरादून में 9 और पौड़ी में 8 जमाती सामने आए हैं।

वहां, मंगलवार को सर्विलांस के माध्यम से दो जमाती हरिद्वार और रुड़की में पकड़े गए उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि लक्सर में चार ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने जमातियों को शरण दी थी।

वहां सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वाले 44 लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

अनिवार्य पास व्यवस्था पर बिफरे कर्मी, बैंक न आने की दी चेतावनी

संवाददाता देहरादून। डीआइजी के बैंककर्मियों के लिए अनिवार्य पास बनाने के निर्देश पर बैंकर्स में रोष व्याप्त है। बैंकर्स ने इस पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि बैंकजह परेशान किया तो वह बैंक नहीं आएंगे।

विगत रविवार को डीआइजी अरुण मोहन जोशी ने कहा था कि बैंक कर्मचारियों के लिए पास अनिवार्य होगा। बैंकर्मी अपने नजदीकी थाने से पास बनाने का समय रखेंगे। इस पर बैंक कर्मियों ने कहा कि रोज सुबह आठ से शाम पांच बजे तक बैंक में काम कर रहे हैं। ऐसे में पास कब और कैसे बनवाएंगे।